भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1489

जिसका उत्तर 27 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

6 अग्रहायण, 1941 (शक)

सूचना प्रौद्योगिकी की उपलब्धता

1489. श्री विजय बघेल:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को और अधिक आसानी से देशभर में उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित/लागू की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा और विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण, पर्वतीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों हेतु आईटी को उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रयास किया है और यदि हां, तो विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार देश में आईटी के विकेन्द्रीकरण हेतु कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया है। डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विविध परियोजनाओं को शामिल किया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात प्रत्येक नागरिक के लिए कोर यूटीलिटी के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग पर शासन और सेवाएं तथा नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। छत्तीसगढ़ सहित ग्रामीण, पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अभिगम को सुलभ बनाने के लिए सरकार शुरु की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

- **सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)** : इसके लिए एमईआईटीवाई ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अतंर्गत अगस्त, 2015 में ''सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)'' 2.0 नामक एक परियोजना प्रारंभ की है जिसमें देश भर की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को शामिल करने के लिए ग्राम पंचायत (जीपी) में कम से कम एक सीएससी स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। सामान्य सेवा केन्द्र ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) नामक स्थानीय उद्यमियों द्वारा संचालित इंटरनेट समर्थित केन्द्र है और ग्रामीण नागरिकों को ई-सेवाएं उपलबध कराते हैं। इन सीएससी के जरिए 350 से अधिक डिजिटल सेवाएं दी जा रही हैं। देश में प्रचालनात्मक सीएससी (शहरी और ग्रामीण) की संख्या 3.64 लाख है, जिसमें से 2.62 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर चालू है।
- **डिजिगांव**: एमईआईटीवाई ने अक्टूबर 2018 में "डिजिटल गांव पायलट परियोजना" की भी शुरुआत की है। इस परियोजना के अंतर्गत देश भर में प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ग्राम पंचायत/गांव के साथ 700 ग्राम पंचायतों (जीपी)/गांवों को शामिल किया जा रहा है। दी जा रही डिजिटल सेवाएं हैं - डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं (सुदूर स्वास्थ्य और सुदूर - पशु चिकित्सा परामर्श), शैक्षिक सेवाएं, (बीसीसी/सीसीसी, टेली पर नाइलिट पाठ्यक्रम) वित्तीय समावेशन जागरूकता कार्यक्रम, कौशल विकास, सौर पैनलयुक्त स्ट्रीट लाइट के साथ-साथ सरकार से नागरिक सेवाएं (जी2सी), व्यापार से नागरिक (बी2सी) सेवाएं। इस परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक ग्राम पंचायत/गांव को शामिल किया जा रहा है ।
- **भारत नेट** : भारतनेट ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड क्रांति शुरू करने के लिए एक महत्वांकाक्षी पहल है। दूर संचार विभाग द्वारा इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारतनेट का उद्देश्य देशभर की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) को जोड़ना और 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अब तक 1,40,668 ग्राम पंचायतों को जोड़ते हुए 3,80,988 कि.मी ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है । 1,28,376 ग्राम पंचायतें सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं।
- **नए युग में शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्प (उमंग)**: आधार, डिजीलॉकर, पेगव, आदि के साथ एकीकृत मुख्य प्लेटफार्म के साथ प्रमुख सरकारी सेवाओं की प्रदायगी के लिए उमंग को एक ही मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में नए युग में शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्प (उमंग) विकसित किया गया है। नागरिक केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और इनकी एजेसियों और कॉर्पोरेट द्वारा दी जा रही कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी सेवाओं तक अखिल भारतीय स्तर पर सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं। 104 विभाग और 21 राज्यों की लगभग 490 सेवाएं उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
- **ई-जिला मिशन मोड परियोजना :** ई-जिला मिशन मोड परियोजना को सभी राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के जिला और उप जिला स्तर पर कार्यान्वित किया गया है, जिसका लाभ सभी नागरिकों को विभिन्न बड़ी मात्रा में ई-सेवाओं जैसे कि प्रमाणपत्र (जन्म, जाति, मृत्यु,आय, और स्थानीय निवासी), पेंशन (वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा), निर्वाचन, ग्राहक न्यायालय, राजस्व न्यायायलय, भूमि रिकॉर्ड और विभिन्न विभागों जैसे कि वाणिज्यिक कर, कृषि, मजदूर रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास इत्यादि की ई-सेवाओं की सुपुर्दगी से से हुआ है। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 721 जिलों में ई-जिला सेवाएं शुरू कर दी गई हैं।

(ग) : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का एक संबद्ध कार्यालय है, जिसके राज्य स्तर पर राज्य केन्द्र और पूरे भारतभर में जिला केन्द्र हैं। ये राज्य और जिला केन्द्र लगातार आईसीटी अनुप्रयोगों में सरकारी अधिकारियों को मार्गदर्शन और सहायता करते हैं। एनआईसी देशभर में अपने उत्पादों और प्लेटफार्मों के जरिए विभिन्न नागरिक केन्द्रीय सेवाएं भी प्रदान करता है।

******